

फूटपर लाइन टाईम्स

<https://futurelinetimes.page>

RNI NO. : UPHIN/2017/72919

आवाज़ दाढ़ की

गौतमबुद्ध नगर से प्रकाशित हापुड़, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ में एक साथ प्रकाशित



● 1.27 लाख करोड़ का उत्पादन, 21 हजार करोड़ के पार पहुंचा एक्सपोर्ट ● यूएस, फ्रांस समेत दुनिया के 100 देशों में एक्सपोर्ट कर रहा डिफेंस उपकरण

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में पिछले एक दशक में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 'मैक इन इंडिया' पहल की शुरूआत के बाद से देश का डिफेंस प्रोडक्शन असाधारण गति से बढ़ा है। यह वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कभी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने वाला देश अब स्वदेशी विनियम में एक उभयता हुई ताकत के रूप में बढ़ा है। भारत घेरे लू क्षमताओं के माध्यम से अपनी



सेव्य ताकत को आकर दे रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन में यह बदलाव आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारत ने सूचित ताकत करता है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करे बल्कि एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रीज भी बनाए जो आर्थिक विकास में योगदान दे। रणनीतिक नीतियों ने इस गति को बढ़ाया है। प्राइवेट पार्टनरिशिप, टेक्निकल इनोवेशन और एडवांस्ड सैन्य प्लेटफॉर्मों के विकास को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। यह आवानिर्भरता प्राप्त करने पर कोरिट्रिट सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन से प्रेरित है।

शपथ ग्रहण के साथ नए मेयरों को मिला बड़ा तोहफा

पंचकूला (एजेंसी)। हरियाणा के पंचकूला में 10 नगर निगमों के मेयर, 28 नगर पालिका-परिषद के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षदों को शपथ दिलाई गई। सरकर पहले अंतिम तापुनाव में मेयर बुरी गई भाजपा की शैलजा सरदार ने शपथ ली। उसके बाद यमुनानगर से सुमन बहमनी, करनाल से रेणुबाला गुप्ता, पानीपत से कोमल सेनी, फरीदाबाद से प्रधान जोशी, गुरुग्राम से राज सरारी, मानसरोवर से निदेलीय डॉ. इंद्रजीत यादव ने शपथ ली।



मेयर, 28 नगर पालिका-परिषद के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षदों का शपथ दिलाई गई। इस दौरान इनकी सेतरी भी बढ़ाई गई है। उसके पहले अंतिम तापुनाव में मेयर बुरी गई भाजपा की शैलजा सरदार ने शपथ ली। उसके बाद यमुनानगर से सुमन बहमनी, करनाल से रेणुबाला गुप्ता, पानीपत से कोमल सेनी, फरीदाबाद से प्रधान जोशी, गुरुग्राम से राज सरारी, मानसरोवर से निदेलीय डॉ. इंद्रजीत यादव ने शपथ ली।

दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट

● यमुना के लिए 500 करोड़ नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए



जाएंगे। यमुना और सीवेंज की सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुर्वान योजना के लिए 2144 हजार करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलाएंगी हैं। साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी और से 5 लाख रुपए जोड़ रही है।

बंगाल में हिंदू और हिंदी बोलने वालों के खिलाफ एक्शन

कोलकाता (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के संस्थान नेता शेष्ठु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सतारुढ़ तुम्हारा मंत्री संघरण पर गंभीर आपरेशन लगाए। उन्होंने समावार को कहा कि टीएमसी मतदाता सुर्यो से फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने की आड़ में हिंदू और हिंदी भाषी मतदाताओं के नाम हटा रही है। संवाददाता



सम्मेलन को संबोधित करते हुए अधिकारी ने दावा किया कि 27 फरवरी के बाद से कई मतदाताओं के नाम मतदाता सुर्यो से हटा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विषय के नेता अधिकारी ने कहा, हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सुर्यो से हटाए जा रहे हैं। मैं निवाचन आयोग से कृष्णनगर के बीड़ीओं को बर्खास्त करने का आग्रह करता हूँ।

92 साल में पहली बार आईएमए में कदम रखेंगी महिला अधिकारी

● सेना में दिखेगा बड़ा बदलाव, एनडीए में 126 महिला कैडेट्स ले रही हैं ट्रेनिंग ● आठ ने सेना में जाने का विकल्प छुना, अलग आवास और ट्रेनिंग की व्यवस्था



काफला बैच मई में ही एनडीए से पास हो जाएगा। अगस्त 2022 में ये महिलाएं एनडीए में बढ़ी हुई थीं। उन्होंने बताया कि एनडीए में इस समय 126 महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग हो रही है। 92 साल में पहली बार

है जब यहां महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी। फिलहाल आईएमए में ही महिलाओं की ट्रेनिंग नहीं होती है। असार 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि महिलाएं भी एस्टोपी की परीक्षा देकर सेना में अधिकारी बन सकती हैं। इससे पहले कुछ चुनी हुई लैंबिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत रखा जाता था। एक अधिकारी ने बताया कि आईएमए में महिला कैडेट्स के रहने के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। वहीं महिलाओं की ट्रेनिंग एनडीए में ही होती है। उन्होंने बाद एक साल अवधि के लिए लिस्ट जारी होती है। उन्होंने तीन साल की ट्रेनिंग एनडीए में ही होती है। उन्होंने बाद एक साल अलग-अलग सेना की जाएगी। वहीं इसके बाद एक साल अलग-अलग सेना की जाएगी।

और पुरुषों की ट्रेनिंग साथ में ही करवाई जाएगी। आईएमए के अधिकारियों ने तैयारी के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चैरिए और एयरपोर्ट एकेडमी डुडील और नेवल एकेडमी का लोग किया। अधिकारी ने कहा कि जिस तरह से 30 साल से आटोएमें में महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग हो जाती है, वैसी ही व्यवस्था आईएमए में भी की जाएगी। बता दें कि यूएपसी एनडीए की हर साल परीक्षा करवाता है। 12 में पहले बाले का पर पास हो चुके स्टॉटेंट इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पास होने पर उन्हें 6 दिन के एस्टोपी की अधिकारी बन सकती है। इससे पहले कुछ चुनी हुई लैंबिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत रखा जाता था। एक अधिकारी ने बताया कि आईएमए में महिला कैडेट्स के रहने के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। वहीं महिलाओं की ट्रेनिंग एनडीए में ही होती है। उन्होंने बाद एक साल अलग-अलग सेना की जाएगी। वहीं इसके बाद एक साल अलग-अलग सेना की जाएगी।

वक्फ बिल के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन की तैयारी, हुंकार आज

● मुस्लिम लॉ बोर्ड आज पटना, 29 को विजयवाड़ा में ऐली करेगा



बनाई गई जाईट पालियामेट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदीप राधिका के बाद अंध्र प्रदेश के विधायिका विभाग व सामाजिक संगठनों के ग्रामीण और प्रांतीय प्रतिनिधि हिस्सों में प्रमुख प्रतिनिधि, दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। भाजपा सांसद और वक्फ बिल संशोधन विधेयक के लिए

जरिस्त वर्मा के घर पहुंची जांच टीम

● स्टोर रुम में गई, यहां 500-500 रुपए के अधिक नोटों से भरी बोरियां मिली थीं



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट के जरिस्त यशवंत वर्मा के लिटियंस दिल्ली स्थित आवास पर मंगलवार दोपहर से आठ बजे 500-500 रुपए के नोटों से भरी अधिजली लॉरियां मिली थीं। जांच टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चौके जरिस्त जरिस्त शील नाम् हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चौके जरिस्त जी एस संधावालिया और कनाटक हाईकोर्ट के जरिस्त अनु शिवराम शामिल हैं। इससे पहले 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉर्टेंग एकलेजियम ने जरिस्त वर्मा को उनके पैरेंट कोर्ट

को हुई बैठकों में सुप्रीम कोर्ट कॉर्टेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जरिस्त यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसेसिंगशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉर्टेजियम के इस प्रसार के प्रसार के लिए लिस्ट जारी होती है। अनिश्चतवालीन हड्डाल पर आपति जारी है। बार आज से अनिश्चतवालीन हड्डाल पर होती है। 23 मार्च को भी दिल्ली हाईकोर्ट के जरिस्त यशव

संपादकीय

केंद्र का सही निर्णय

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला के तहत एल्युमीनियम फॉयल सहित पांच चीनी बस्तुओं पर एंटी डॉपिंग ड्यूटी लगाया है। बताया जा रहा है कि यह निर्णय घेरेलू उद्योगों को चीन से सस्ते आयात के निषेटिव असर से बचाने के लिए की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर (व्यापार उपचार महानिदेशालय) की सिफारिश के आधार पर व्यापार कार्रवाई की गई है। डीजीटीआर डॉपिंग और सब्सिडी जैसे मामलों की जांच करती है। दरअसल, एंटी-डॉपिंग ड्यूटी आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैक्स हैं, जो उनके निर्वात मूल्य और उनके सामान्य मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई के लिए लगाए जाते हैं, अगर डॉपिंग के कारण आयात करने वाले देश में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादकों को नुकसान होता है। केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात लंबे अरसे से थी कि चीन भारत के घेरेलू उद्योग को बर्बाद करने की साजिश में लगा हुआ है। आखिरकार सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। स्वाभाविक तौर पर सरकार के इस फैसले से भारतीय उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार को भी यह भरोसा है कि ऐसी सख्ती से भारतीय उद्योगों को मदद मिलेगी। इससे वे चीन से आने वाले सस्ते आयात से मुकाबला कर पाएंगे। भारत ने पहले ही चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात से निपटने के लिए कई उत्पादों पर डॉपिंग रेटी शुल्क लगाया है। इन सब तथ्यों से इतना तो साफ होता है कि चीन की नीतय में खोट है। वह भारत से मिलने वाली तमाम रियायतों और सुविधाओं को दरकिनार कर उसी का नुकसान पहुंचाने की जुगत में लगी रहती है। हो सकता है इस कदम के बाद चीन इस बात की संवेदनशीलता को समझेगा। ऐसे भी भारत के बाजार पर चीन के सामानों की बहुतायत है। कोई भी त्योहार मसलन दीपावली हो या होली; चीन किफायती कीमत के उत्पाद भारत में भेजता है। उसके इस कदम से भारत में काम कर रही कंपनियों की सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पर केंद्र की नेन्द्र मोदी सरकार के फैसले की सराहना की जानी चाहिए। घेरेलू उद्योगों को जीवनदान देने के लिए यह एहतियाती कदम उठाना लाजिमी था। इस बात में कोई शक नहीं कि चीन सिफर अपना फायदा देखता है। उसके शब्दकोष में न तो संवेदना की जगह है और न नैतिकता की। इस नाते मोदी सरकार की यह पहल ऐतिहासिक मानी जाएगी।

चिंतन-मन्त्र

प्रकाशस्त्रोत परमात्मा

८५

दि नांक 21 से 23 मार्च तक बंगलूरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में दशहरा के पावन पर्व पर हुई थी, और इस प्रकार संघ अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है एवं इस वर्ष दशहरा के शुभ अवसर पर ही अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा। संघ की स्थापना विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में राष्ट्रीयत्व का भाव जागृत करने एवं हिंदू समाज के बीच समरसता स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर हुई थी। इन 100 वर्षों के अपने कार्यकाल में संघ ने हिंदू समाज को एकजुट करने में सफलता तो हासिल कर ही ली है साथ ही विशेष रूप से समाज की सज्जन शक्ति में राष्ट्रीयत्व का भाव पैदा करने में सफलता अर्जित की है। सज्जन शक्ति समाज की वह शक्ति है कि जिनकी बात समाज में गम्भीरता से सुनी जाती है एवं उस पर अमल करने का प्रयास भी होता है। संघ ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं की स्थापना की थी। इन शाखाओं में देश की युवा पैदी में राष्ट्रीयत्व का भाव जगाकर ऐसे स्वयंसेवक तैयार किए जाते हैं जो समाज के बीच जाकर देश के आम नागरिकों में राष्ट्र भावना का संचार करते हैं एवं समाज के बीच समरसता का भाव पैदा करने का प्रयास करते हैं। संघ द्वारा स्थापित की गई शाखाओं की कार्यपद्धति पर आज विश्व के अन्य कई देशों में शोध कार्य किए जाने के बारे में सोचा जा रहा है कि किस प्रकार संघ



प्रह्लाद संष्करणा

की बात की जा रही है। प्रशासकीय व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था में जबरिया हिंदी थोपने की बात कही जा रही है। तमिलनाडु इसे राज्यों की स्वतंत्रता पर केंद्र का हमला बता रहा है। भारतीय सर्विधान राज्यों को अपनी भाषा के आधार पर नीतियां बनाने की अनुमति देता है। तमिलनाडु में हिंदी का प्रचलन पिछले दशकों में बढ़ता चला जा रहा है। स्कूलों में भी हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। जिस तरह से हिंदी भाषा को केन्द्र सरकार द्वारा अनिवार्य किया जा रहा है। उसके कारण एक बार फिर हिंदी के विरोध में दृष्टिक्षण के राज्य खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु में अभी 2 स्तरीय भाषा फार्मूला है। जिसमें तमिल और अंग्रेजी की अनिवार्यता है। तमिलनाडु सरकार का मानना है, यहां की शिक्षा व्यवस्था के लिए यही दो भाषा पर्याप्त हैं। केंद्र सरकार को यदि तीन भाषाओं का फार्मूला लागू करना था। तो इसमें हिंदी संस्कृत एवं अन्य भाषाओं को ऐच्छिक रखा जाना चाहिए था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर एक बार फिर भाषा को लेकर केंद्र एवं राज्यों के बीच में तकरार शुरू हो गई है। पहली बार 1937 में हिंदी को अनिवार्य किए जाने की काव्यत शुरू हुई थी। मद्रास प्रेसीडेंसी की कंग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया था। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया था। तत्कालीन जस्टिस पार्टी और पेरियार ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिए थे। 1940 में यह नीति वापस ले ली गई थी। उसके बाद 1965 में भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के प्रावधान के तहत हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया। उस समय भी दृष्टिक्षण के राज्यों में इसका भारी विरोध हुआ। भाषा का विवाद राज्यों के पुर्णांठन के समय भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला था। भाषा के आधार पर ही कई राज्यों का गठन हुआ। जब-जब भाषा विवाद हुए हैं, उसमें हिंदा भी हुई है। भाषा एक ऐसा विषय है, जिसको लेकर नागरिक भावात्मक रूप से भाषा के पक्ष में खड़े होते हैं। जब-जब भाषा को राजनीति का हिस्सा बनाया जाता है। इसका व्यापक असर जन सामान्य के बीच देखने को मिलता है। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला को लेकर जो शिक्षा नीति बनाई गई है। उसने एक बार फिर राज्यों को भाषा के आधार पर उद्देशित कर दिया है। तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आगे चलकर अन्य गैर हिंदी भाषा के राज्यों में भी इस तरह के विवाद उग्र हो सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में भाषा को लेकर इस तरह का विवाद कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता है। एआई के इस दौर में जब किसी भी भाषा

भाषा विवाद राष्ट्रीयता के लिए खतरा, हिन्दी भाषा को नुकसान

की बात की जा रही है। प्रशासकीय व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था में जबरिया हिंदी थोपने की बात कही जा रही है। तमिलनाडु इसे राज्यों की स्वतंत्रता पर केंद्र का हमला बता रहा है। भारतीय संविधान राज्यों को अपनी भाषा के आधार पर नीतियां बनाने की अनुमति देता है। तमिलनाडु में हिंदी का प्रचलन पिछले दशकों में बढ़ता चला जा रहा है। स्कॉलों में भी हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। जिस तरह से हिंदी भाषा को केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य किया जा रहा है। उसके कारण एक बार फिर हिंदी के विरोध में दर्शक्षण के राज्य खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु में अभी 2 स्तरीय भाषा फार्मूला है। जिसमें तमिल और अंग्रेजी की अनिवार्यता है। तमिलनाडु सरकार का मानना है, यहां की शिक्षा व्यवस्था के लिए यही दो भाषा पर्याप्त हैं। केंद्र सरकार को यदि तीन भाषाओं का फार्मूला लागू करना था। तो इसमें हिंदी संस्कृत एवं अन्य भाषाओं को ऐच्छिक रखा जाना चाहिए था। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर एक बार फिर भाषा को लेकर केंद्र एवं राज्यों के बीच में तकरार शुरू हो गई है। पहली बार 1937 में हिंदी को अनिवार्य किए जाने की कवायत शुरू हुई थी। मद्रास प्रेसीडेंसी की कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया था। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बढ़ते कदम

A photograph showing a group of men marching in a procession. They are dressed in white shirts, brown trousers, and black turbans. Some are wearing sunglasses. They are carrying long wooden sticks or poles. The background shows a street with trees and some buildings. The men appear to be in uniform, possibly members of a paramilitary or a specific cultural group.



स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है। आज विश्व के 53 देशों में 1,604 शाखाएं एवं 60 साप्ताहिक मिलन कार्यरत हैं। पिछ्ले वर्ष 19 देशों में 64 संघ शिक्षा वर्ग लगाए गए। विश्व के 62 विभिन्न स्थानों पर संस्कार केंद्र भी कार्यरत हैं। जर्मनी से इस वर्ष 13 विस्तारक भी निकले हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भारत से नई उड़ान भर रहे युवाओं को जोड़ा जाता है ताकि एक तो विदेशों में इनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके तथा दूसरे इनमें सनातन संस्कृति के भाव को जागृत किया जा सके। साथ ही, इन युवाओं के भारत में रह रहे बुजुर्ग माता पिता से भी सम्पर्क बनाया जाता है। संघ के स्वयंसेवक भारत में इनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास भी करते हैं। भारत में धार्मिक पर्यटन पर आने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की सहायता भी संघ के स्वयंसेवकों द्वारा किए जाने का प्रयास किया जाता है तथा भारतीय मूल के नागरिक यदि भारत में वापिस आकर बसने के बारे में विचार करते हैं तो उन्हें भी इस सम्बंध में उचित सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाता है।

बांग्लादेश के बदलते सुरों को गंभीरता से लेना होगा

बा ग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कहा कि हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं। बस कुछ गलतफहमियां हैं, जिन्हें दूर करने की काशिश की जा रही है। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली स्थिति में यूनुस किन रिश्तों के मजबूत होने की बात कर रहे हैं, कैसी गलतफहमियां और किनके द्वारा उत्पन्न गलतफहमियों की बात वे कर रहे हैं? यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने भारत से दूरियां बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां हिन्दुओं एवं हिन्दू मन्दिरों पर कहर बरपाया गया, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कवायद करते हुए भारत को डराने की कोशिशें हुई, कट्टरपंथी एवं जिहादी ताकतों को सहयोग, समर्थन और संरक्षण दिया गया है, इन सब स्थितियों को उपर से उग्रतर बनाकर अब यूनुस किन रिश्तों की बात कर रहे हैं, वे क्यों बैंकॉक में आयोजित होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं? बांग्लादेश का भारत-विरोधी रवैया दुर्भग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि विडम्बनापूर्ण बना है। भारत से पंगा बांग्लादेश को कितना महंगा पड़ रहा है, इसका अनुमान बांग्लादेश की बिगड़ती अर्थ-व्यवस्था, शांति-व्यवस्था एवं अराजकता को देखते हुए सहज ही लगाया जा सकता है। इन ज्वलंत होती स्थितियों का सबसे बड़ा कारण भारत से दुश्मनी ही है। बांग्लादेश में अराजकता, हिंसा एवं जर्जर होते हालात को मोहम्मद यूनुस सरकार नियन्त्रित नहीं कर पा रही हैं। मुल्क अपी भी भीड़ की हिंसा की उन घटनाओं से उबर नहीं रहा है, जो पिछले अगस्त में शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन के बाद शुरू हुई थी। यूनुस से क्षेत्र में शांति व सद्व्यवहार की जो उम्मीदें थीं, उसमें उन्हाँन मुस्लिम कट्टरपंथ को आगे करके निराश ही किया है। उनकी सरकार लगातार विघटनकारी, अडियल व बदमिजाजी का रुख अपनाए हुए है। यदि भारतीय प्रधानमंत्री बैंकॉक में यूनुस से वातालाप करते हैं तो उन्हें उनके इरादों को लेकर सतर्क एवं सावधान

भारत ग्रांट्स से बांग्लादेश का सहयोगी एवं हितेशी रहा है, इसी कारण उसने पिछले डेढ़ दशकों में जो आर्थिक तरकी हासिल की, छह फीसदी से अधिक दर से जीडीपी को बढ़ाया और 2026 तक विकासशील देशों के समूह में शामिल होने का सपना देखा, उन सब पर मोहम्मद यानुस की अगुवाई वाली अंतर्राष्ट्रीय सरकार के संकीर्णतावादी एवं त्याजाही स्त्री के काम्या काली

उत्तराखण्ड के काठगोड़ का नाम
छाया मंडराने लगी है।
बांगलादेश में भारत विरोधी
वातावरण तैयार किया जा
गया, वहाँ हिन्दुओं एवं अन्य
अल्पसंख्यकों पर हमले की
घटनाओं पर भारत की तमाम
चिंताओं के बावजूद गंभीरता
नहीं दिखाई गयी और
अल्पसंख्यक हिन्दुओं के दमन
को रोकने के लिए वांछित
कदम उठाने से इनकार किया
गया है।



रोकने के लिए वांछित कदम उठाने से इनकार किया गया है। इन सब स्थितियों के कारण आज वहाँ कानून-व्यवस्था के सामने समस्या पैदा हो गई है, बांग्ला राष्ट्रवाद की वकालत करने वालों पर खतरा मंडराने लगा है, प्रगतिशील मुस्लिमों एवं अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और बंगबंधु व मुक्ति संग्राम के इतिहास को मिटाने का प्रयास हो रहा है। बांग्लादेश की यह गति इसलिए हुई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप चुनौतियों से लड़ पाने में नाकाम रहे हैं और भारत से टकराव मोल लेकर उन्होंने अपने पांचों पर खुद कुल्हाड़ी चलाई है। बांग्लादेश के हुक्मरानों और विशेषतः यूनुस सरकार ने विवाद के नये-नये मुद्दे तलाश कर दोनों दैशों के आपसी संबंधों को नेस्तनाबूद किया है। आज वहाँ सांविधानिक, सार्विक, सैन्यात्मक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में ऐसी

वहां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है और वह बांग्लादेशी सेना के हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। चीन ने ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशिया में भारतीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में इस्तेमाल किया है और वह इस्लामाबाद की मदद से बांग्लादेश में भी अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान को अतिश्येकिपूर्ण ढंग से अपने आतंरिक मामलों में जगह देकर बांग्लादेश ने खुद खतरा मौल लिया है। पाकिस्तान भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश का उपयोग करता है। वह आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए भी बांग्लादेश का उपयोग करता है। इसी के चलते अंतर्रिम सरकार के प्रमुख के रूप में यूनुस ने कई कट्टपंथी संगठनों से प्रतिबंध हटाया है और आतंकी गतिविधियों के लिए आरोपित नेताओं को जेल से रिहा भी किया है। भारत को इसकी भी अनदेखी नहीं करना चाहिए कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के दखल का मुख्य ध्येय भारत को कमजोर एवं अशांत करना ही है। यूनुस का कार्य व्यवहार चिंतित करने वाला है। वह यथाशीघ्र चुनाव कराने में रुचि दिखाने के बजाय ऐसे एंजेंडे अपने हाथ में ले रहे हैं, जिससे लंबे समय तक सत्ता में बना रहा जाए। अब तो बांग्लादेशी की सेना भी यूनुस के खैरेये को लेकर सर्वोक्तु दिख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध जिन छात्रों के विद्रोह के चलते यूनुस बांग्लादेश की अंतर्रिम

सरकार के प्रमुख बने, उन छात्रों ने पिछले दिनों नेशनल सिटिंग्ज़ पार्टी नाम से अपना अलग दल गठित कर लिया और यह आरोप भी लगाया कि सेना शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की साजिश रच रही है। यह चकित करने वाला घटनाक्रम है। इसलिए और भी, क्योंकि बांग्लादेश की सेना ने इस पार्टी के आरोपों को हास्यास्पद और निराधार करार दिया। भारत को बांग्लादेश के घटनाक्रम पर इसलिए निगाह रखनी होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि छात्रों की इस नई पार्टी के गठन के पीछे यूनुस का ही हाथ है। बांग्लादेश में आंतरिक स्थिति जटिल से जटिलतर होती जा रहा है, स्थितियां विकराल हो रही हैं, आम जनता पर दुःखों, परेशानियों एवं समस्याओं के पहाड़ टूटने लगे हैं। वहां जैसी आंतरिक गुटबाजी, प्रशासनिक शिथिलताएं, अराजकताएं और अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमाने सेना की भूमिका बढ़ाने की बात कही है। उनका सकेत साफ है, यदि अंतरिम सरकार हालात को संभाल पाने में नाकाम रहती है, तो सेना मोर्चा संभालने को तैयार है।

भारत के सहयोग से हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी और वह जीडीपी वृद्धि कर रहा था। लेकिन उनके तख्तापलट के बाद से विकास में तेजी से गिरावट आई है और देश मंदी की ओर बढ़ रहा है। विश्व बैंक और आईएमएफ का कहना है कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश की विकास-दर आधी हो गई है और उसका कपड़ा उद्योग-जो उसके विकास का आधार था-बेरोजगारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन अंतरिम सरकार मौजूदा स्थिति के लिए हसीना सरकार को दोषी ठहराती है, यह बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति है। लेकिन यह तय है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां, बांग्लादेश का भारत विरोध और पाकिस्तान प्रेम इस मुल्क पर भारी पड़ रहा है। भले ही 54 सालों में पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान सीधा कारोबार शुरू हुआ है। देखेने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध सामान्य नहीं हैं और व्यापार ठप्प है। ऐसे में इसका असर भारत पर नहीं पाकिस्तान पर जरूर पड़ा है और वहां की जनता त्राहित्राहि कर रही है। बांग्लादेश के लिए भारत जो मायने रखता है, उसकी भरपाई पाकिस्तान तो कर्तव्य नहीं कर सकता है। जिस बांग्लादेश को पाकिस्तानी कूरता से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने तमाम कुर्बानियों के बाद जन्म दिया, वही बांग्लादेश व्या सोचकर भारत से दूरियां बढ़ाई? अब अपनी गलती का अहसास करते हुए वह भारत से दोस्ती चाहता है तो भारत को सरकारी, सावधानी, दूरगमी सोच, कूटनीतिक सोच से कदम उठाने चाहिए।

